

मुनाफे पर संकट, नई रणनीति बुनने लगीं कंपनियां



शाइन जैकब
चैन्सई, 31 जुलाई

अपराह्न की ओर से भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने का समाजना का असर दिखाना शुरू हो गया है, जिससे भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर खत्म हो रहे हैं। तिरपुर-जैसे हब में कंपनियां नियांतकों का कहना है कि अमेरिका पहले ही 10 प्रतिशत तक की छूट की मांग कर रहा है और भारतीय नियांतकों से वह शुल्कों के कारण पड़ने वाले वित्तीय बढ़ा का कुछ हिस्सा वहन करने का आग्रह कर रहा है।

ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय नियांतकों को बड़ी मात्रा में जाने वाले सामान्य उत्पादों पर औसतन 5 प्रतिशत तक का ही मुनाफा मिलता है। फैक्टरी उत्पादों पर यह लगभग 20 प्रतिशत होता है। भारत से वॉलमार्ट, टारप, एयरजॉन, कॉस्टको, मेसोंज़, गैप और कोलंबिया स्पोर्ट्सवर्कर, जैसे अमेरिकी ब्रांड सामान मांगते हैं। टैरिक की मार ऐसे समय पड़ी है जब इस साल जनवरी से मई के बीच अमेरिकी बाजार में भारतीय परिधानों की अयात हिस्सेदारी एंटरप्राइज दर्ज की गई है, जो इससे पिछले वर्ष इसी अवधि में 6 प्रतिशत पर थी। बाइंग एंटरप्राइज एसोसिएशन के अध्यक्ष और एसएनक्यूएस इंटरनेशनल के प्रबंध नियांतक इलांगोन विश्वनाथन ने कहा, 'कुछ ब्रांडों ने पहले से ही 10 प्रतिशत तक की छूट मांगनी शुरू कर दी है।' इंडियन टेक्सरेन्स फेडरेशन (आईटीएफ) के संयोजक प्रभु दामोदरन ने कहा, '25 प्रतिशत शुल्क के बावजूद भारत को लागत के मामले में वॉलमार्ट और कॉलंबिया से 10 प्रतिशत, श्रीलंका से 5 प्रतिशत और चीन से 20-25 प्रतिशत अधिक लाभ है।' कच्चे माल और इससे जुड़ी अन्य वस्तुओं में हमारी मजबूत नीत तथा बेहतर होती आपूर्ति व्यवस्था के कारण हमें वैश्विक स्तर पर अधिक पर्सनल किया जाता है।' उद्योग से जुड़े कंपनियों का कहना है कि काफी कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि चीन टैरिक किस स्तर पर नियांतर होता है, क्योंकि वैश्विक व्यापार में अलग-अलग प्रतियांधीस्तक लाभ काफी मायने रखता है। कपड़ा निर्माता टीटी लिमिटेड के प्रबंध नियंत्रक संजय कुमार जैन ने कहा, 'बढ़ते टैरिक के कारण अगले तीन महीनों तक खरीद धीमी रहेगी, लेकिन अमेरिका के पास पर्याप्त माल नहीं है, जिससे अधिक इंतजार बढ़ती कर सकता।'

उन्होंने यह भी कहा, 'भारत के पास वैसे भी आज नियांत में 10 प्रतिशत से अधिक की छूट की क्षमता नहीं है। वह अभी क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में है।' किसी अन्य देश के मुकाबले ट्रिनें और वे खरीदार पहले माल लेना चाहें, जिन्होंने हर हाल में भारत से अधिक माल लेने का फैसला किया है।'

शुल्क की चिंता से नए नियांते स्तर पर रुपया

पृष्ठ 1 का शेष

सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के एक डॉलर ने कहा, 'आयातकों और विदेशी पोर्टफोलियो नियांतकों द्वारा डॉलर की खरीद की वजह से रुपये में नरमी आई है।' उन्होंने कहा, 'भारतीय रिजर्व बैंक ने 87.75 प्रति डॉलर पर हस्तक्षेप किया। रुपये में अगे भी नरमी बढ़ी रह सकती है और निकट अवधि में 87.90 प्रति डॉलर की रुपये देखा जा सकता है।'

विज़नेस स्टैंडर्ड के सर्वेक्षण के अनुसार रुपये में भारी उत्पाटक रहने की उम्मीद है। सर्वेक्षण में शामिल ज्यादातर प्रतियांधीस्तकों ने कहा कि सिर्वेक्षण तक रुपया 88 प्रति डॉलर के करीब पहुंच सकता है।

व्यापार तनाव उभरते बाजार को मुरामों पर दबाव डालना जारी रखेगा, जिससे रुपया नए नियांते स्तर की ओर बढ़ रहा है और निकट अवधि में इसमें गिरावट बढ़ी रह सकती है। हालांकि दिसंबर के अंत तक डॉलर के मुकाबले रुपये में सुधार होने की उम्मीद है।

आईआईआईआई बैंक में इकनोमिक्स रिसर्च के प्रमुख समीक्षा नारंग ने कहा, 'भारत पर जो शुल्क लगाया गया है उसका असर पड़ा है। रुपया अन्य देशों की तुलना में भारत पर लगाए गए अंतर्कात्मक अधिक शुल्क पर प्रतिक्रिया दे रहा है।' इस महीने रुपये में करीब 2.3 फीसदी की गिरावट आई है। दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। इन रुपयों को देखते हुए हमारा मानना है कि अंतर्कात्मक मुरामों पर दबाव बना रहेगा। फिलालू मध्यम अवधि का दृष्टिकोण इस बात पर नियांतर करेगा कि शुल्क का मुद्दा कैसे आगे बढ़ता है।

इस बीच अमेरिकी फैक्ट्री बैंक में इकनोमिक्स रिसर्च के प्रमुख समीक्षा नारंग ने कहा, 'कैंप ऑफ बड़ौदा के मुख्य अंतर्कात्मक मदन सबनवीस ने कहा, 'मुझे सिंतंबर तक और गिरावट की उम्मीद है।' लेकिन इसके बाद सुधार होगा। दिसंबर अंत रुपया 87 और 88 प्रति डॉलर के बीच कागजार कर सकता है।'

रुपये पर सर्वेक्षण

बैंक	सिंतंबर अंत	दिसंबर अंत
आईआईआई बैंक	87\$/1-88.50/\$1	x
आईएफसी फर्स्ट बैंक	88/\$1	87/\$1
कर्सर वैश्व बैंक	86.80/\$1-87.00/\$1	86.20/\$1-86.50/\$1
क्रिसिल एस	x	87.50/\$1
सीआर फॉरेक्स	86.20/\$1-88.50/\$1	85.50/\$1-90/\$1
शिनहान बैंक	86.20/\$1-88.70/\$1	85.60/\$1-87.95/\$1
बैंक ऑफ बड़ौदा	86.50/\$1-87/\$1	87/\$1-88/\$1
एचडीएफी बैंक	87.00/\$1-88.00/\$1	86/\$1-87/\$1
मेकलाई फाइनैशियल सर्वे	86.50/\$1	88.00/\$1
फिनरेक्स द्वेरा एडवाइजर	86.80/\$1	87.80/\$1

जीडीपी में गिरावट संभव: बार्कलेज

वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी बार्कलेज ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका की तरफ से भारत पर 25 प्रतिशत सीमा शुल्क और जुमाना लगाए जाने से चालू वित्तीय में देश की सकल घटू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में 0.30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

बार्कलेज ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत बंद प्रकृति और घेरेतु मांग पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस शुल्क वृद्धि का व्यापक असर पड़ने की आशंका नहीं है।'

बार्कलेज के मुताबिक, यह शुल्क वृद्धि 1 अगस्त से लगाए जाने से वाले वित्तीय में देश की अपेक्षाकृत बंद प्रकृति और घेरेतु मांग पर नियर्थता इसे बढ़े झटकों से बचाती है। हमारा मानना है कि 25 प्रतिशत शुल्क का प्रभाव सीमित रहेगा और जीडीपी वृद्धि पर इसी अवधि तक होगा।'

इसी के साथ ही एल्यूमीनियम, स्टील और वाहन जैसे उत्पादों पर मौजूदा क्षेत्र-विशिष्ट शुल्क भी लागू रहते हैं तो भारतीय अयात पर कुल प्रभावी अमेरिकी शुल्क (जुमाने को छोड़कर) लगभग 26.6 फीसदी है।

भारतीय अवधि में देश की अपेक्षाकृत बंद प्रकृति और घेरेतु मांग पर नियर्थता इसे बढ़े झटकों से बचाती है। हमारा मानना है कि 25 प्रतिशत और जीडीपी वृद्धि पर इसी अवधि तक होगा।'

रूस से घटा, अमेरिका से बढ़ा तेल आयात

पृष्ठ 1 का शेष

गोल्डमैन सैक्स ने आज एक रिपोर्ट में कहा, 'अगर नए शुल्कों को लागू किया जाता है, साथ ही एल्यूमीनियम, स्टील और वाहन जैसे उत्पादों पर मौजूदा क्षेत्र-विशिष्ट शुल्क भी लागू रहते हैं तो भारतीय अयात पर कुल प्रभावी अमेरिकी शुल्क (जुमाने को छोड़कर) लगभग 26.6 फीसदी है।'

बालांकि सिंगापुर की ऊर्जा विशेषज्ञता वंदना हारि ने कहा कि आगे मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि भारत पर यूरोपीय संघ (ईयू) और अमेरिका दोनों पर प्रतिबंध बढ़ रहे हैं। वंदना इनसाइट्स की संस्थापक हारि ने स्वतंत्र अनुसंधान डोटा का हवाला देते हुए कहा कि भारत को रुसी तेल पहुंचाने वाले टैक्टर में से करीब 20 फीसदी पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है।

दो सरकारी रिपाइनिंग अधिकारियों ने कहा कि ट्रैक्टर के द्वारा जारी नहीं है कि रोसेपेट की इकाई नायरा एनजी यूरोपीय संघ के प्रतिबंध के बाद कैसे परिचय दिल्लीवारी के लिए बदल देती है।

नायरा ने विशिष्ट योजनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

हिस्सेदारी 3 फीसदी थी। यह ऊर्जा नियांतर के द्वारा प्राप्ति विशेषज्ञता पैदा हो गई है। इसका अनुवर्धन अंत में हुआ था और अब वह यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की ओरोंपार समुद्र में है।

हालांकि सिंगापुर की ऊर्जा विशेषज्ञता वंदना हारि ने कहा कि आगे मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि भारत पर यूरोपीय संघ (ईयू) और अमेरिका दोनों पर प्रतिबंध बढ़ रहे हैं। वंदना इनसाइट्स की संस्थापक हारि ने स्वतंत्र अनुसंधान डोटा का हवाला देते हुए कहा कि भारत को रुसी तेल पहुंचाने वाले टैक्टर में से करीब 20 फीसदी पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है।

दो सरकारी रिपाइनिंग अधिकारियों ने कहा कि ट्रैक्टर के द्वारा जारी नहीं है कि रोसेपेट की इकाई नाय